

के विचार से की गयी है न कि सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के लिये, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के राजस्व में कुछ वृद्धि हो सकती है।

अमरीकी सहायता

3853. श्री भोकार लाल बेरवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरीका ने भारत को किन किन क्षेत्रों में सहायता देना बन्द कर दिया है ; और

(ख) उस कमी को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) और (ख). दिसम्बर 1971 में, संयुक्त राज्य ने भारत को देय विकास ऋणों के एक भाग को देना बंद कर दिया था और उसने मई 1973 में फिर से विकास ऋण देना शुरू कर दिया था। 1972 और 1973 के वर्षों में अमरीका से कोई नया विकास ऋण नहीं मिला।

अमरीकी सहायता बन्द किये जाने के बाद देशी उत्पादन में वृद्धि करने, आयात प्रतिस्थापन की गति तेज करने तथा निर्यात बढ़ाने के लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं। जिन मामलों में आयात करना अनिवार्य है उनमें, अन्य ऋणों के अन्तर्गत तथा हरया अदायगी क्षेत्रों से माल उपलब्ध करने के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाया जा रहा है और जिन मामलों में ऐसा करना संभव नहीं है, उनमें यथासंभव सीमा तक मुक्त विदेशी मुद्रा का आवंटन किया जा रहा है।

नियन्त्रित कपड़े की कीमत में वृद्धि

3854. श्री भोकार लाल बेरवा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नियन्त्रित कपड़े की कीमत में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो कब और कितनी ; और

(ख) इस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख): नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन, वितरण तथा कीमतों के संबंध में विद्यमान प्रणाली के संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है।

Independent Organisation for dealing in Import Trade of Dry Fruits

3855. SHRI D. B. CHANDRA GOWDA:
DR. H. P. SHARMA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that huge profit has been made by the fruit traders recently before and after Dewali connection with the sale of dry fruits; and

(b) if so, whether Government are in a position to set up an independent organisation for dealing in import trade of dry fruits; and if so, the broad outlines thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI A. C. GEORGE): (a) and (b). It is proposed to canalise the import of dry fruit through the S.T.C. in order to ensure its supply to consumers at reasonable prices.